Parimal Nathwani
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

Member:
Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice
Consultative Committee, Ministry of Commerce and Industry
Permanent Special Invitee:
Consultative Committee, Ministry of External Affairs

सत्यमेव जयते

165, South Avenue,
New Delhi - 110 011
Ph.: 011-23794010
e-mail : parimal.nathwani@sansad.nic.in

' Vraj ', Opp. HDFC Bank,
Beside Chandanbala Tower,
Nr. Suvidha Shopping Centre,
Paldi, Ahmedabad - 380 007

प्रेस विज्ञप्ति

मल्टी-सेक्टरल विकास कार्यक्रम को जिला-केन्द्रीत के बजाय प्रखण्ड स्तर का बनाएं

राज्य सभा सांसद नथवाणीजी ने केन्द्रीय स्तर पर प्रदेश के मुस्लिम समुदाय की आवाज को मुखर किया

मार्च 22, 2011 : राज्य सभा सांसद श्री परिमल नथवाणी ने कल नई दिल्ली में केन्द्रीय लघुमती कार्य मंत्री श्री सलमान खुरशीद द्वारा बुलाई गई बैठक में झारखण्ड के लघुमती समुदाय की चिंता को मुखर किया। आपने कहा कि मल्टी सेक्टरल विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.) का अधिक विस्तार किया जाए और उसे जिला स्तर से प्रखण्ड स्तर पर लाया जाए ताकि वह अधिक कारगर ढंग से लागू हो सके और फण्ड का समुचित उपयोग हो सके।

सच्चर समिति की सिफारिशों एवम् अवलोकनों के मद्देनजर आयोजित यह बैठक मुस्लिम समुदाय की समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए आयोजित की गई थी। इस बैठक में बाद में प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह और योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मान्टेक सिंह अहलूवालिया ने भी शिरकत की।

बैठक में अपने उद्‌बोधन के दौरान श्री नथवाणी ने कहा कि जिला कलक्टर पर काम के अतिशय बोज के कारण एम.एस.डी.पी. के कार्य को प्रखण्ड स्तर तक विकेन्द्रीत किया जाए या कोई नोडल एजन्सी बनाई जाए ताकि विकास कार्यक्रम सफल हो सके। आपने कहा कि प्रदेश में जो मुस्लिम-बहुल जिले हैं वहां शैक्षणिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य नागरिक सुविधाओं की स्थिति अतिशय खराब है जिन पर ध्यान दे कर सुधार किया जाना जरूरी है। आपने कहा कि उर्दू स्कूलों एवम् मदरसों के अध्यापक माहवार 900 रुपए में काम करते हैं; एक एक क्लास-रूम में दो-दो कक्षाओं के छात्रों को बिठाया जाता है; जो कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। बैठक में श्री नथवाणी ने यह भी कहा कि झारखण्ड अभी

नया राज्य राज्य है और एम.एस.डी.पी. फण्ड की राशि के 38.51 का ही उपयोग वहां हो रहा है। अगर इस कार्यक्रम को ढंग से विस्तारित कर के प्रखण्ड स्तर तक लाया जाए तो इस में अधिक जनसंख्या को समाहित किया जाएगा और फण्ड का समुचित उपयोग भी हो सकेगा। इससे छः जिलों के बजाए 13 जिले और 44 प्रखण्डों के मुस्लिम समुदाय को लाभ मिलेगा; ऐसा भी आपने कहा।

सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट में देश के विभिन्न राज्यों के उन 90 जिलों की सूची दी है जिनमें मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक है। इन जिलों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी में ऐसे जिले हैं जहां की सामाजिक-आर्थिक एवम् मूलभूत सुविधाओं के संकेतक राष्ट्रीय औसत से कम हैं। झारखण्ड के साहिबगंज एवम् पकौर इस श्रेणी में आते हैं। दूसरी श्रेणी में ऐसे जिले हैं जहां या तो सामाजिक-आर्थिक सुविधाएं या फिर मूलभूत सुविधाएं राष्ट्रीय औसत से कम हैं। रांची (खूंटी सहित) एवम् गुमला (सिमडेगा सहित) इस श्रेणी में हैं। इतना ही नहीं, झारखण्ड के हजारीबाग, रांची, मंगो, गिरिडीह, भुली, झरिया और झोरपकर ऐसे नगर हैं जहां मुस्लिम लघुमती की जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक है।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अहलूवालिया ने बैठक के दौरान अपने प्रतिभाव में श्री नथवाणी एवम् अन्यों द्वारा उठाए मुद्दों को विशेष रूप से नोट किया। श्री नथवाणी ने बैठकोपरान्त मंत्री महोदय श्री खुरशीदजी को एक पत्र भी दिया जिसमें आपने झारखण्ड के मुस्लिमों के लिए बेहतर शैक्षणिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं की आवश्यकता पर बल दिया। पत्र में आपने हजरत महम्मद पयगम्बर साहब को उद्धृत किया जिसमें पयगम्बर ने कहा था कि : ''शिक्षा के लिए अगर चीन जाना पड़े तो भी जरूर जाओ।''

★ ★ ★